

## माननीय प्रधान मंत्री डॉ.मनमोहन सिंह जी का संबोधन\*

रिज़र्व बैंक में आना हमेशा ही प्रसन्नता की बात रही है। ऐसे स्थान पर आना विशेष बात है जो किसी का अपना घर रहा हो। यह बात और भी प्रसन्नतादायक हो जाती है जब उसके साथ किसी की सुखद और मधुर यादें जुड़ी हुई हों। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए मुंबई एक दूसरे घर के रूप में रहा है और भारतीय रिज़र्व बैंक से मेरे अपने कार्यकाल के बहुत ही यादगार क्षण जुड़े हुए हैं।

मुझे रिज़र्व बैंक के 1967-81 तक के इतिहास के तीसरे खंड का विमोचन करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। केंद्रीय बैंक के लिए वे वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष थे जिनके दौरान बैंकों का राष्ट्रीकरण हुआ, वित्तीय क्षेत्र का उल्लेखनीय विस्तार तथा उसके कार्यों में विविधता और उच्च मुद्रास्फीति के युग के दौरान मौद्रिक नीतियों के लिए संघर्ष जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं।

प्रकाशित तीनों खंडों को जिनमें 1935-1981 तक की अवधि समाहित है, अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उनमें वास्तव में भारत के आर्थिक उत्कर्ष का इतिहास और हमारी वित्तीय संस्थाओं की परिपक्वता दिखाई देती है। इस अवसर पर मैं भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नरों, जैसे सी.डी.देशमुख, एल.के.झा, एस.जगन्नाथन, आई.जी.पटेल, आर.एन.मल्होत्रा और सी.रंगराजन एवं डॉ. बिमल जालान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस महान संस्था के विकास और उत्कर्ष में अपना योगदान दिया है। संस्थाओं के इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें समय की आकार देने वाली घटनाओं में संस्थाओं की भूमिका का रिकार्ड होता है। परंतु इतिहास केवल घटनाओं का रिकार्ड ही नहीं होता है। उपयोगी इतिहास घटनाओं के आगे और पीछे भी अन्वेषण करता है और उसका विश्लेषण करते हुए उस समय की लोक नीति बनाने और उनको आकार देने तथा उस समय की राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों का संस्थाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका मूल्यांकन करने में संस्थाओं द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन भी करता है। मुझे विश्वास है कि रिज़र्व बैंक के 1935-1981 के बीच के कार्यों का वर्णन करनेवाले इन तीनों खंडों का न केवल ऐतिहासिक महत्व होगा बल्कि समसामयिक औचित्य भी होगा।

केंद्रीय बैंकों की भूमिका, 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना से शुरू होकर बहुत समय में विकसित हुई है। यह व्यापक तौर पर माना जाता है कि सेंट्रल बैंक का प्रमुख कार्य मौद्रिक और वित्तीय स्थायित्व को

बनाए रखना है। तथापि, विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों को अपनी सक्रिय भूमिका के द्वारा विकास और वृद्धि के संवर्द्धन की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी निभानी होती है। दो दशक पहले जब मैं रिज़र्व बैंक का गवर्नर था तब मेरा ध्यान इस बात पर गया था कि “देश के केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्राधिकरण की नीतियों का आधुनिक अर्थव्यवस्था की कार्यपद्धति पर बहुत ही गहरा असर होता है”<sup>1</sup> और हमारी मौद्रिक और ऋण नीतियों का उद्देश्य राष्ट्र के समग्र सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए।<sup>2</sup> इस संभावना को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने समाज के विविध वर्गों को पर्याप्त मात्रा में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कीमत और वित्तीय स्थिरता बनाए रखकर आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में योगदान दिया है। इसके अलावा रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण, ग्रामीण सहकारिता और विकास, वित्त संस्थाओं के विकास जैसी अपनी गैर परंपरागत जिम्मेदारियों को भी सफलतापूर्वक निभाया है। रिज़र्व बैंक की भूमिका के इन पहलुओं को इतिहास के इन खंडों में भलीभांति दर्ज किया गया है जिनका आज विमोचन किया जा रहा है।

सन 1990 के दशक के दौरान बदले हुए हालात में, रिज़र्व बैंक को समष्टि आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए और अधिक व्यापक भूमिका निभानी थी। 1990 के दशक के प्रारंभ में अप्रत्याशित रूप से भुगतान संतुलन के संकट के बाद इस देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास की संभावनाओं में उसकी दक्षता के विकास के लिए संरचनात्मक सुधार शुरू किए गए। इन सुधारों ने बहुत ही सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है। सुधार के बाद की अवधि में, भारत समष्टि आर्थिक स्थायित्व के वातावरण में उच्चतर वृद्धि दर प्राप्त करने में सफल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में शुरू किए गए संरचनात्मक सुधारों के प्रमुख घटक वित्तीय और बाह्य क्षेत्र के सुधार रहे हैं और इन दोनों क्षेत्रों में रिज़र्व बैंक ने सरकार के साथ समन्वय रखते हुए बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है।

### मूल्य स्थिरता

अनेक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करने पर भारतीय मुद्रास्फीति को, आपूर्ति में बारबार आघात पहुंचने के बावजूद, संतोषजनक

\* भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में 18 मार्च 2006 को भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिहास के तीसरे खंड के विमोचन के अवसर पर।

1 & 2 “भारतीय रिज़र्व बैंक की ऋण नीति” महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद, मुंबई द्वारा 18 नवंबर 1982 को आयोजित समारोह का स्वागत भाषण।

माना जा सकता है। यद्यपि 1970 के दशक के दौरान मुद्रास्फीति बढ़ी थी और उसके बाद 1990 के दशक के मध्य तक ऊंची बनी रही जिससे राजकोषीय स्थिति में बड़ा विस्तार हुआ था, उसके बाद की अवधि में मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति के अनुमानों में उल्लेखनीय कमी आई है। इसका श्रेय विवेकशील मुद्रास्फीति नीतियों को जाता है। वास्तव में, मुद्रास्फीति की दर पिछले दशक में 5% से कम के औसत पर बनी रही। यह बहुत ही संतोष की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद हम स्फीति की दर को कम और इन स्फीतिकारी अनुमानों को सीमित रखने में कामयाब रहे हैं।

### मौद्रिक राजकोषीय परस्पर संबंध

देश भर के अनुभव बताते हैं कि कीमतों की स्थिरता को बनाए रखने की सफलता, मौद्रिक राजकोषीय परस्पर संबंध और राजकोषीय विवेकशीलता पर निर्भर होती है। मैंने दो दशक पहले ऐसा देखा था कि “1974-75 और 1980-81 के दौरान के भारतीय अनुभवों से स्पष्ट होता है कि स्फीतिकारी रुख को रोकने में सक्रिय मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। परंतु यदि मौद्रिक प्रतिबंध से वांछित संभाव्य उत्पादन में कमी किए बिना उद्देश्यों को प्राप्त करना हो तो मौद्रिक नीति के ऊपर अत्यधिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय प्रणाली इस प्रकार परिचालित की जाए कि लोक व्यय के वित्तपोषण के लिए रिज़र्व बैंक से ऋण लेने पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जाए।” हालांकि इस पहलू को 1970 और 1980 के दशकों के दौरान मान लिया गया था परंतु केवल सुधारों के उपरान्त 1990 के दशक के दौरान ही भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति के परिचालन में लचीलापन महसूस कर पाया। प्रमुख नीतिगत विकास जिसने मौद्रिक नीति के पर्यावरण को और स्वतंत्र बनाया, वह 1997 में सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच हुए एक समझौते के जरिए सरकार के राजकोषीय घाटे को स्वचालित रूप से धन मुहैया करने के कार्य को बंद करना था।

इसको और अधिक शक्ति वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम) के पास हो जाने से मिली। 2006-07 से रिज़र्व बैंक को प्राथमिक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को रखने की अनुमति नहीं होगी। समस्त स्तर पर स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय मुद्रा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार राजकोषीय समेकन के रास्ते पर चलने के लिए कटिबद्ध है। विवेकशील राजकोषीय नीति मौद्रिक नीति द्वारा वहन किए जानेवाले बोझ को हल्का करती है। राजकोषीय नियमों का पालन करने से स्फीति के अनुमानों का प्रबंध करने, स्फीति को कम रखने तथा स्थिर रखने में मदद मिलेगी।

अब बहुत ही व्यापक रूप से यह माना जा रहा है कि सबसे अच्छा मार्ग जिसके जरिए मौद्रिक नीति वृद्धि और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करा सकती है, वह है - कीमतों की स्थिरता - जिसे कम और स्थिर स्फीति कहा गया है। स्फीति प्रतिगामी बोझ है जिसकी मार गरीबों पर सबसे ज्यादा पड़ती है। इसलिए कीमतों की स्थिरता हमारी जैसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां गरीब जनता के बड़े भाग के पास स्फीति के बचाव के लिए कोई आश्रय नहीं है।

### वित्तीय स्थिरता

यद्यपि कीमतों की स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। 1970 के दशक के प्रारंभ में अर्थव्यवस्था के खुले हो जाने के साथ वित्तीय स्थिरता की बात, भारत में मौद्रिक नीति निर्माण के संदर्भ में अब दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा है। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि भारतीय रिज़र्व बैंक देश में, यहां तक कि अर्थव्यवस्था के 1990 के दशक के पूर्वार्द्ध से ही उदारीकरण की प्रगति के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सफल रहा है। इस मामले में भारत का रिकार्ड विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि 1990 का दशक तो अधिकतर उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय क्षेत्र में बहुत ही उथल-पुथल वाला रहा है। भारत में 1990 के दशक में शुरू किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का उद्देश्य विविधीकृत, चुस्त और प्रतियोगी वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देना था और सुधार उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। विनियमन हटाए गए वित्तीय क्षेत्र के वातावरण में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, जबकि कई अन्य देशों में इससे बचा गया, हमारी सफलता का श्रेय एक तरफ अर्थव्यवस्था में उचित कीमत की स्थिरता सुनिश्चित करने में प्राप्त सफलता को जाता है और दूसरी तरफ वित्तीय और बाह्य क्षेत्र के प्रबंध से संबंधित विवेकशील नीतियों को जाता है।

### बाह्य क्षेत्र प्रबंध

देश में अर्थव्यवस्था का बाह्य क्षेत्र प्रबंध समष्टि स्तर पर अर्थव्यवस्था के प्रबंध की एक अधिक उल्लेखनीय सफलता रही है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आवक को वरीयता के साथ पूंजी खाते को खोलने में भारत ने बहुत ही सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है जबकि अल्पावधि ऋण के आगमन पर जोर नहीं दिया है और पूंजी खाते के उदारीकरण को कुछ पूर्व शर्तों पर आश्रित एक प्रक्रिया मानते हुए कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय संकटों के आलोक में उचित प्रमाणित किया गया है। पूंजी की आवक के संबंध में सतर्क दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से वांछित था क्योंकि पूंजी की आवक से पूंजी के जाने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपेक्षाकृत पूंजी आवक के स्थायी घटक को आकृष्ट किया जाए और परिवर्तनशील घटक पर ज्यादा जोर न दिया जाए। साथ ही, यह भी जरूरी

है कि विदेशी मुद्रा के भंडार को परंपरागत आयात कवर के निर्धारण से अधिक बढ़ाया जाए। विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार निर्मित करने की भारत की नीति ने वित्तीय स्थायित्व को बनाए रखने और अर्थव्यवस्था में लचीलापन प्रदान करने में योगदान किया है।

वर्ष 2001-2004 के दौरान मध्यम स्तर का अधिशेष भंडार दर्ज करने के बाद भारत का चालू खाता शेष, अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग में उछाल आने के कारण वांछित स्तर से घाटे में चला गया। भारत के वणिज्य निर्यात में सेवाओं के निर्यात के साथ साथ, बहुत ही सुदृढ़ वृद्धि हुई है। तेल से इतर आयात की मांग अधिक रही। इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर चालू खाता घाटा स्वयं में चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि हमारा चालू खाता घाटा अभी भी अच्छी स्थिति में है जिसकी पूर्ति सामान्य पूंजी आवक के द्वारा आसानी से की जा सकती है।

अंततः, हमारी विनियम दर नीति बड़े पैमाने पर बाजार द्वारा निर्धारित विनियम दर है जिसका केंद्र बिंदु परिवर्तनशीलता की प्रवृत्ति को व्यवस्थित करने पर है, समय के साथ कसौटी पर खरी उतरी है। विनियम दर के प्रबंध में भारत का अनुभव और अधिक लोचदार और व्यावहारिक होकर प्रबंध करने पर केंद्रित है।

अंत में, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में स्थिरता और वित्तीय क्षेत्र के आधुनिकीकरण दोनों के बारे में 1990 के दशक में हमने जिन सुधारों की शुरुआत की थी, उनकी सफलता हमारी आशाओं से अधिक रही है। कीमतों और वित्तीय स्थिरता को बरकरार रखते हुए सुधारों को लागू करने में एवं गहरे संकट के समय बाह्य क्षेत्र को सुदृढ़ ढंग से निर्माण करने में अपना योगदान देकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हमारे सामने बड़ी-बड़ी चुनौतियां हैं। वृद्धि को और आगे बढ़ाना होगा। गरीबी को तेजी से कम करना होगा। रोजगार को और तेजी से बढ़ाना होगा। हमारे किसानों और लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र दोनों की ऋण आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना होगा। हमारी बैंकिंग प्रणाली को भी असंगठित क्षेत्र की ऋण की मांग को वाजिब लागत पर पूरा करने के लिए पर्याप्त ध्यान देना होगा। यह हमारा राष्ट्रीय एजेंडा है। भारतीय रिज़र्व बैंक को भी इस राष्ट्रीय एजेंडे को आगे बढ़ाने में योगदान करना है।

आज, वैश्वीकरण कई सुपरिचित मामलों को उसी तरह से बदल रहा है जिस तरह से हम सोचते हैं, कार्य करते हैं और निष्पादन करते हैं। यह सेंट्रल बैंकिंग को भी बदल रहा है। भारी मात्रा में धन देश से बाहर विदेशों में बहुत आसानी से और तेजी से भेजा जाने लगा है। वैश्वीकरण की इन ताकतों के मद्देनजर वित्तीय स्थिरता बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। परंतु वैश्वीकरण एक अवसर भी है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ाने में वैश्विक स्तर पर पूंजी जुटाने के लिए निवेश

की तलाश संभव बनाने में मदद करता है। देश के लिए वैश्वीकरण की लागत घटाने और उससे होनेवाले लाभों को बढ़ाने में रिज़र्व बैंक को आगे रहना होगा।

मुंबई को क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र बनाने के प्रस्ताव पर पहले से ही सक्रिय विचार हो रहा है। हमारे आर्थिक सुधारों ने वृद्धि को तीव्र किया है, स्थिरता को बढ़ाया है और बाह्य तथा वित्तीय दोनों क्षेत्रों को सुदृढ़ता प्रदान की है। हमारे व्यापार और वित्तीय क्षेत्रों का पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारी मात्रा में एकीकरण हो गया है और वह प्रवृत्ति अब पीछे मुड़नेवाली नहीं है। मुंबई, अपने सभी अंतर्निहित लाभों, मानव पूंजी और वित्तीय समझदारी के कारण संभाव्य क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र बनने की स्थिति में है। हमें इस उद्देश्य की तरफ काम करना चाहिए।

पिछले दो दशकों में हुए परिवर्तनों के मद्देनजर अब पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनियता की ओर बढ़ने में ही समझदारी है। इस मामले पर सबसे पहले तारापोर समिति में विचार किया गया था। उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। आंतरिक और बाह्य रूप से हमारी अपनी स्थिति बहुत ज्यादा आरामदायक हो गई है। इसलिए मैं वित्त मंत्री और रिज़र्व बैंक से अनुरोध करता हूँ कि वे इस विषय में दुबारा विचार करें और वर्तमान वास्तविकता के आधार पर योजना तैयार करें। इस मामले में की गई प्रगति से मुंबई के न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक वित्तीय केंद्र के रुपांतरण में भी मदद मिलेगी। हमारे पास विशेष आर्थिक क्षेत्र समेत बहुत से विकल्प हैं जो ऐसे केंद्र के लिए संभव हैं। मुझे विश्वास है कि हम इस मामले में धीरे-धीरे परंतु ठोस प्रयत्न कर सकेंगे। राज्य सरकार को इसके लिए विशेष रूप से भौतिक बुनियादी ढांचे के रूप में उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित करना होगा।

बड़ी और शीघ्रता से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत में विश्व स्तर की रुचि बढ़ रही है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के उभरने के पीछे जो प्रेरक बल है वह हमारी कुशलता और काम करने की हमारे कार्य बल की क्षमता है। हमें न केवल इसको बनाए रखना होगा बल्कि सेवा क्षेत्र में अपेक्षाकृत और सुधार करना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय सेवाएं एक प्रमुख सेवा उद्योग के रूप में उभरी हैं। साथ ही, भारतीय वित्तीय बाजारों का वैश्विक प्रणाली के साथ एकीकरण और कुछ नए वित्तीय उत्पादों को शुरू किए जाने में जोखिम प्रबंध तथा वित्तीय इंजीनियरिंग की कुशलता की आवश्यकता है। इससे विनियामक संस्थाओं के ऊपर भी नया बोझ पड़ेगा। अतः वित्तीय क्षेत्र में लगे कर्मिकों की कुशलता को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है।

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय रिज़र्व बैंक के छत्र के अंतर्गत कार्य करनेवाली अग्रणी संस्थाओं में से एक है। बहुत तेजी से बदलते हुए परिवेश के मद्देनजर और भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती शक्ति के

कारण एक ऐसे संस्थान की परम आवश्यकता है जो बैंकिंग और वित्त से संबंधित क्षेत्रों की नीति के बारे में अनुसंधान केंद्र का कार्य करे। बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय इस भूमिका को निभाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अतः बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय अब से नीति-उन्मुख संस्था के रूप में अपनी छवि बनाएगा और बीटीसी का “प्रगत वित्तीय अध्ययन केंद्र” के रूप में पुनर्नामकरण करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में यह केंद्र बैंकिंग और

वित्त के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित होगा। मैं इस केंद्र की चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए शुभ कामना करता हूँ। अर्थव्यवस्था पर अपने स्पष्ट विचार व्यक्त करने में रिज़र्व बैंक की स्वतंत्र भूमिका तथा मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयोजन से बनाई गई नीतियों की उद्दिष्ट प्राप्ति हमारी अर्थव्यवस्था प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं।

इन कार्यों को पूरा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं।